एक संतुलित बढ़त

लेखक - सैयद जफर इस्लाम (बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व प्रबंध निदेशक, ड्यूश बैंक, मुंबई)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

30 अगस्त, 2019

"भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व बेहतर स्थिति में हैं और विकास में भी वृद्धि जारी है।"

अगर आज आप निवेशकों के लिए वैश्विक बाजारों को देखेंगे, तो दो बड़े ब्लॉक सबसे पहले याद आएंगे, जिसमें पहला है भारत और दूसरा अफ्रीका है। अप्रत्याशित रूप से, इन उभरते बाजारों ने पिछले दो दशकों में अधिकतम विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। भारत, इन दो में से बड़ा होने के नाते, विदेशी निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा बना हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत को पिछले छह वर्षों में 250 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो 2014 से पहले के 14 वर्षों में विदेशी निवेश के बराबर है। वर्तमान में, भारतीय कॉरपोरेट जगत में यह विश्वास थोड़ा कम दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उनकी चिंता है जहाँ जीडीपी की 60 से 70 बीपीएस कम होने की संभावना है।

कई विश्लेषकों का मानना है आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये का बड़ा अधिशेष सौंपकर एक जिम्मेदार कदम उठाया है। यह राष्ट्रीय हित में है क्योंकि इससे सरकार को न केवल संभावित आर्थिक मंदी का मुकाबला करने में मदद् मिलेगी, बल्कि यह हर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने में भी मदद् करेगा।

सरकार अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत से अधिक की विकास दर पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए निजी क्षेत्र ने थोड़ी सुस्ती दिखाई है। हमारे निजी क्षेत्र और वास्तव में अर्थशास्त्रियों को पता था कि मोदी-1 द्वारा एक मजबूत, आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है। यह थोड़ा अनियमित हो सकता है, लेकिन इसका लाभ लंबे समय तक फलदायी रहेगा।

कई लोगों का दावा है कि उच्च वृद्धि के लंबे समय के बाद दुनिया की छठी अग्रणी अर्थव्यवस्था में थकान देखने को मिलेगी। 6.30% की अनुमानित दर पर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है। एक तिमाही में 5.8 प्रतिशत की इतनी प्रभावशाली वृद्धि दर से डर नहीं लगना चाहिए।

हाँ, मंदी है। लेकिन हमने अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है।

मोदी-1 को एक बड़े पैमाने पर अनौपचारिक, विस्तृत नकदी अर्थव्यवस्था, अराजक असंगठित क्षेत्र विरासत में मिला था। बेशक, भारत 1990 के सुधारों के बाद मान्यता से परे बदल गया था, लेकिन आर्थिक गतिविधि के बड़े हिस्से अतीत में गुलाम बने हुए थे। मोदी सरकार ने अभी तक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। विमुद्रीकरण और जीएसटी दो बड़े बदलाव थे, जो राष्ट्रीय हित में थे।

एक अन्य कारक जिसने मंदी में योगदान दिया है वह हाल के दिनों में सामान्य से कम हुई वर्षा है (हालांकि, इस वर्ष मानसून अच्छा है)। दुर्भाग्य से, इस कारक को आम तौर पर बहस में अनदेखा कर दिया जाता है। चुनावों में मंदी का भी योगदान हो सकता है। चुनावों के दौरान आचार संहिता के कारण, सरकार योजनाओं पर खर्च करने या बड़े सुधारों की घोषणा करने में

असमर्थ थी। नतीजतन, पूंजीगत व्यय की वृद्धि 12 प्रतिशत की पिछली तिमाही से 2 प्रतिशत तक गिर गई और जीडीपी लगभग 80 बीपीएस तक प्रभावित हुई। भारत की मंदी वैश्विक प्रवृत्ति से भी मजबूती से जुड़ी हुई है और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध भी मंदी में बखूबी योगदान दे रहा है।

हमारी अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छे पायदान पर है। हमारे मैक्रो संकेतक सभी अच्छे हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर विचार करते हैं:- विदेशी मुद्रा भंडार 491 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर है; CPI मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत पर है और यह लगभग 12 महीनों से 4 प्रतिशत के निशान से नीचे है। कोर मुद्रास्फीति भी पिछले 12 महीनों में सार्थक रूप से कम हो गई है। सकल एफडीआई प्रवाह, जीडीपी के 12 प्रतिशत के आधार पर 2.4 प्रतिशत के करीब है।

पीएमआई विनिर्माण और सेवाओं के लिए जुलाई में पिछले महीने में मंदी की तुलना में सुधार देखा गया। यह उत्साहजनक है और यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है तथा इससे रोजगार सृजन में भी तेजी आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव ने पिछले कुछ दशकों में इतनी ऊर्जा पैदा की है कि जिससे कुछ दशकों से एक मजबूत गति बनी हुई है। यह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह एक संवाददाता सम्मेलन में कई स्वागत योग्य उपायों की घोषणा की और मंगलवार को एक और बैठक में समस्या को हल करने के अपने संकल्प को दोहराया।

उद्योग से संबंधित कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ऋणदाताओं और उधारकर्त्ताओं के बीच तथा सरकार एवं उद्योग के बीच विश्वास की कमी थी। उन्होंने सरकार से इस पर गौर करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री ने ठीक ऐसा ही किया। पीएसयू बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की राहत से बाजार में खुशहाली लाएगी। सरकार कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन शुरू कर रही है, जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करना, आदि।

अच्छे मानसून के बाद सरकार का खर्च बढ़ने वाला है। त्यौहारी सीजन में प्रवेश करते ही खपत बढ़ जाएगी। यह निर्यात में सुधार से, निवेश से और विनिवेश से आएगा। सरकार, निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, जैसा कि बजट में भी घोषित किया गया है। विदेशी निवेशकों के शेयरों में वृद्धि हुई है। यह विदेशों से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए बाध्य है। हमारा मानना है कि सरकार इस वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य को पार कर सकती है, जो 1.14 लाख करोड़ रुपये है।

पूर्वानुमान अगली तिमाही और उससे आगे के लिए बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है, लेकिन हाँ, यह तुरंत दोहरे अंकों में परिवर्तित नहीं होगी। पीएम मोदी के सुधारों, ऋण प्रवाह और व्यापार करने में आसानी और उनके संक्रामक आशावाद पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ इसकी भी संभावना है कि हम औसत जीडीपी 7.5 प्रतिशत रखते हुए और डॉलर के मुकाबले रुपये को 70 के आस पास स्थिर रखते हुए 2024/2025 तक 5-ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

GS World
Committed to Excellence

भारत में मंदी के आसार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर है। निर्मला ने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है।
- उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है।

क्या कहा उन्होंने?

1. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दीवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
2. वित्तमंत्री ने टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न खत्म करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा, अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा।

- टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा। टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी रिटर्न एवं रिफंड को और आसान बनाया जाएगा।

3. सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का कैपिटल तुरंत मिलेगा, ताकि बैंक, बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें।
4. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा ; भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा। एमएसएमई की एक ही परिभाषा बनाई जाएगी।
5. बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है ; रेपो रेट या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए। बैंक, घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे।
6. सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी जल्द लाएगी। मार्च, 2020 तक खरीदे गए BS-4 तकनीकी के वाहन रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे।
7. सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता भी उपलब्ध कराएगी, जिससे कुल समर्थन राशि 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी।
8. सरकार ने ऋण प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है।
9. सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर लगाया गया ऊँचा कर अधिभार वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है।
10. सरकार ने एंजेल टैक्स को खत्म किया।

आर्थिक मंदी क्या है?

- जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम तीन महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- चीनी आयात में मंदी के परिणामस्वरूप कुछ देशों (विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों) को नुकसान हो रहा है, जो विभिन्न घटकों (Components) सहित अन्य तैयार माल तथा 'सप्लाई वैल्यू चेन' के लिये चीन पर निर्भर हैं।
- विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र के उन देशों के लिये यह एक झटका होगा, जो चीन को कच्चे माल का निर्यात करते हैं।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस ट्रेड वॉर में पहले से ही जीडीपी का कम-से-कम 0.1% का नुकसान हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता चीनी वस्तुओं पर बढ़े हुए टैरिफ का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ रही है।

सीएसआर क्या है?

- जैसा कि हमें पता है कि कम्पनियाँ किसी उत्पाद को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं और अपनी जेबें भरती हैं; लेकिन इस खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधियों के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इन प्रभावित लोगों को कंपनियों की तरफ से किसी भी तरह का सीधे तौर पर मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- इस कारण ही भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे अपनी आमदनी का कुछ

भाग उन लोगों के कल्याण पर खर्च भी करें, जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कहा जाता है।

भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में कौन कौन आता है?

- भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के नियम 1 अप्रैल, 2014 से लागू हैं। इसके अनुसार जिन कम्पनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो, तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है।
- यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। CSR नियमों के अनुसार, CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते हैं, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनी की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. आर्थिक मंदी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरन्तर गिरावट को आर्थिक मंदी कहा जाता है।
2. जब सकल घेरलू उत्पाद कम-से-कम तीन महीने डाउन ग्रोथ में हो तो आर्थिक मंदी के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements regarding Economic Slowdown-

1. Continuous decline in the production of goods and services internationally is called Economic Slowdown.
2. When the GDP is in at least three months of down growth, it is known as Economic Slowdown.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत उन उभरते बाजारों में से एक है जिसने पिछले दो दशको में सर्वाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। इस हेतु वर्तमान सरकार द्वारा अपने प्रथम कार्यकाल में किए गए प्रयासों एवं वर्तमान में मंदी को देखते हुए तथा अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत से अधिक की विकास दर पर वापस लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. India is one of the emerging markets that has attracted world's foreign investment in the last two decades. In this context, discuss the efforts made by the present government in its first term and in view of the present slowdown and the efforts being made to bring the economy back to more than eight percent growth rate. (250Words)

नोट : 29 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।